Name	Capacity	Estimated Cost (Rs. in crores)	Remarks
Bargarh Canal (H)	5x2.1 = 11	12.0	Returned to State in September, 1988 for resubmission of the revised report based on various CEA/CWC comments and modifying the IC to 3x3 MW instead of 5x2.2 MW and updating the cost estimates.

formulation of sub-Committee on power to review the working of NPCC

2993. SHRI GURUDAS DAS GUPTA:

SHRI CHATURANAN MISHRA;

Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a Sub-Committee of the Parliamentary Consultative Committee on power has been formed to review the working of the State owned National Projects Construction Corporation (NPCC); and

(b) if so, what are the details in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF POWER IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRI KALPNATH RAI). (a) and (b) Pursuant to the decision taken by the Consultative Committee for the Ministry of Energy in their meeting held on 3rd February. 1989, a Sub-Committee of the Consultative Committee has been constituted to go into the various point relating to the working of the National Projects Construction Corporation, raised by the Members of the Committee at the aforesaid meeting. The Composition of the Sub-Committee is as follows: —

1. Shri R. P. Panika, M.P. Chairman
2. Shri Anil Basu, M. P. Member
3. Shri Salahuddin, M. P. Member
4. Shri Damodar Pandey, M .P. Member
5. Shri Jagannath Patnaik, M. P. Member
6. Shri Sarfaraz Ahmed, M. P. Member

The term of the Sub-Committee *is* for a period of six months from the date of the Notification.

देश में लम्बित पड़ी ट्रांसमिशन लाइन परियोजनाएं

2994. **श्री राम जेठमलानी :**
सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :

क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में कई ट्रांसमिशन लाइन परियोजनाएं स्वीकृति के लिए लम्बित पड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो उन परियोजनाओं के नाम क्या-क्या हैं और ये परियोजनाएं विचारण के लिए कब से लम्बित पड़ी हैं; और

(ग) इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए प्राथमिकता के आधार पर सरकार द्वारा कोई कार्यवाही न किए जाने के क्या कारण हैं?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) कुछ पारेषण लाइन परियोजनाएं परीक्षण की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में जिन महत्वपूर्ण परियोजनाओं की तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से जांच की जा रही है, उनका ब्यौरा अनुपत्र में दिया गया है। [देखिए परिशिष्ट 149, अनुपत्र सं० 163]

(ग) परियोजनाओं का कार्यान्वयन, पूर्ण परियोजना रिपोर्ट तैयार करना और सम्बन्धित परियोजना प्राधिकारियों द्वारा सभी प्रासंगिक सूचनाओं/स्पष्टीकरणों को उपलब्ध कराया जाना तथा उनमें विभिन्न मंजूरियों और स्वीकृतियों को प्राप्त करने/सुनिश्चित करने पर निर्भर करना है। ट्रांसमिशन लाइनों को, सम्बद्ध विद्युत केन्द्रों से बिजली के पारेषण के लिये जोड़ा जाता है और सरकार द्वारा इस बात के लिये भरपूर कोशिश की जाती है कि दोनों को चालू करने में किसी प्रकार की व्यवस्था का अभाव न हो।

ट्रांसमिशन लाइनों के निर्माण के लिए संस्थान की स्थापना

2995. **श्री राम जेठमलानी :**
सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने एक नये संस्थान की स्थापना करने का निर्णय किया है जोकि एक स्थान से दूसरे स्थान तक विद्युत के संचरण के लिए ट्रांसमिशन लाइनों के निर्माण तथा उनकी देखभाल के लिए पूर्णतः उत्तरदायी होगा ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संस्थान की स्थापना किए जाने से विद्युत विभाग का वित्तीय भार और बढ़ जाने की संभावना है ;

(ग) क्या सरकार ने विद्युत आवश्यकता के आधार पर वितरण के लिए एक राष्ट्रीय ग्रिड की स्थापना किए जाने के प्रस्ताव को छोड़ दिया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो अब तक उक्त ग्रिड के स्थापित न किए जाने के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (घ) अतिरिक्त उच्च वोल्टता लाइनों का केन्द्रीय क्षेत्र में सतत रूप से विस्तार करने और अन्तरराज्यीय एवं अन्तरक्षेत्रीय पारेषण लाइनों के निर्माण/उन्हें सशक्त बनाने से एक राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड के विकास की धारणा को प्रोत्साहन मिला है। एक राज्य/क्षेत्र से दूसरे राज्य/क्षेत्र में विद्युत के पारेषण के लिये अतिरिक्त उच्च वोल्टता लाइनों के संरूपण, निर्माण, रख-रखाव एवं प्रचालन के लिये राष्ट्रीय स्तर पर एक अलग संगठन बनाये जाने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता। तथापि, इस सम्बन्ध में समस्या के सभी पहलुओं के सघन अध्ययन किये जाने की आवश्यकता है, जिसमें प्रस्तावित संगठन की स्थापना भी शामिल है। क्षेत्रीय ग्रिड इस प्रकार के राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड के अंग होंगे।

Suggestions for mobilizing funds for power development by Punjab, Haryana and Delhi chambers of commerce and Industry

2996. SHRI BHAGATRAM MANHAR;

SHRI BIR BHADRA PRATAP SINGH:

Will the Minister of ENERGY be pleased to state;

(a) whether it is a fact that Punjab, Haryana and Delhi Chambers of Commerce and Industry have suggested for mobilizing more funds and expertise for the development of power in the country;

(b) whether it is also a fact that PHDCCI has prepared a paper""entitled "Energy Scenario in the Northern Region" highlighting the various methods for the improvement in the energy sector; and

(c) if so, what are the details there_ of and what is the reaction of Government on the various suggestions made by the PHDCCI?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF POWER IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRI KALPNATH RAI): (a> and (b) Yes. Sir.

(c) The discussion paper prepared by the Punjab, Haryana and Delhi